संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) :(क) जी, हां।

(ख) 31-3-89 और 31-3-92 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 14,19,556 और 22,86,593 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे।

(ग) वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के दौरान 16,35,726 टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) दूरसंचार विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) तैयार की है जिसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :

— ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में वस्तुत: मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

—बड़ी टेलीफोन प्रणालियों के अर्न्तगत टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष तकसीमित करना।

विस्तार योजनाएं तदनुसार तैयार की जा रही हैं।

पुरानी पिन-कोड निदेशिका और एस. टी. डी. कोड

1965. **मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी** : क्या संचार मंत्री 21 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1173 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकतर डाकघरों में उपलब्ध पिन-कोड निदेशिका बहुत पुरानी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में बिक्री-काउंटरों पर काफी समय से पिन-कोड निदेशिका उपलब्ध नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ङ) क्या यह सच है कि देश में अधिकतर तार कार्यालयों में प्रदर्शित किए गए एस.टी.डी. कोड अद्यतन स्थिति नहीं दर्शाते, जिससे ग्राहकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। डाकघरों में जो पिनकोड निदेशिका उपलब्ध है वह पुरानी नहीं है क्योंकि विभिन्न डाकघरों को जो पिनकोड नम्बर पहले आवंटित किए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। निर्देशिका का वर्तमान संस्करण छपने के बाद वितरण डाकघरों में बदले गए कुछ नये डाकघरों के पिनकोड नम्बर शामिल किए जाने हैं। यह नम्बर शामिल किए जा रहे हैं और नई निर्देशिका छप रही है।

(ग) और (घ) छपाई में विलंब के कारण डाकघरों में, जिनमें दिल्ली के डाकघर भी शामिल हैं, बिक्री के लिए पिनकोड निर्देशिका की कमी है। पिनकोड निर्देशिका का छपाई में विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि इसे देखने के प्रयोजन से आसान बनाने के लिए इसके फारमेट में परिवर्तन किया गया। पिनकोड डायरेक्टरी का नया संस्करण संशोधित फारमेट में भुवनेश्वर स्थित विभागीय मुद्राणालय में छप रहा है।

(ङ) और (च) चूंकि, नेटवर्क में नए एस. टी. डी. स्टेशन निरंतर जुड़े रहे हैं, इसलिए नए एस.टी.डी. रूट को चालू करने और देश के सभी केन्द्रीय तारघरों/ विभागीय डाकघरों को कोड आदि की सूचना देने के बीच समय का कुछ अंतर पड़ जाता है।

दूरसंचार सर्किलों को यह निदेश जारी किए गए हैं कि वे तीन महीने के अंतराल पर एस.टी.डी. कोड की सूची को अद्यतन बनायें और इसे अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी तारघरों को भेजें ।

Lending of Unaccounted Money to Small Scale Units

@1966. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Federation of Association of Small Industries of lhdia has suggested to Government to float a scheme, under which individuals and firms could lend their unaccounted money to the small-scale units; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) A suggestion to this effect has been received. There is no proposal to float a scheme for attracting black money to the small scale units, for the present.

Negative impact of W. B. Assistance on Indian Private Enterprise

1967. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank assistance totalling 20 billion dollars from 1951 to 1989 has
harmed the country's private enterprise according to a new study as referred in the news item entitled
'WB aid has stifled private initiative' which appeared in the Hindustan Times' dated the 30th June, 1992;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) The news item mentioned in the Question refers to a study on World Bank assistance to India. Numerous Institutes conduct studies which are not referred to Government of India and it is not, therefore, possible to comment on the same. However as far as World Bank's assistance to India between 1951 to 1989 is concerned, the same has been committed! for a large number of development projects in different sectors consistent with national policies and priorities.

Foreign Capital Investment in India

1968. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Miinster of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the break up of foreign capital invested in the country during the years 1990, 1991 and 1992 so far;

(b) whether Government are aware that some foreign investors are of the view that the recent re forms are too late and too little; and

(c) if so, what steps Government propose to take in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) According to the Reserve Bank of India, data on actual foreign investment in the country is available only up to 1990. In the following table, actual data on foreign investment for 1990 is given. Data for 1991 and January- April , 1992 is on the basis of approvals given.

@Previously Unstarred Question 796, transferred from the 16th July, 1992.